



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 7, 2008/वैशाख 17, 1930

No. 167]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 7, 2008/VAISAKHA 17, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2008

विषय: चीन जन. गण., थाइलैंड तथा वियतनाम से पॉलिस्टर के सभी फुली ड्रॉन या फुली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (एफ डी वाई) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत ।

फा. सं. 14/13/2008-डी जी ए डी.— यतः मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि, मै. गुप्ता सिंथेटिक्स लि., मै. नोवा पेट्रोकेमिकल्स लि० और मै० चिरिपाल इंडस्ट्रीज लि० की ओर से कृत्रिम फाइबर उद्योग एसोसिएशन (जिसे एतदपश्चात आवेदक कहा गया है) ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात नियमावली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन गण, थाइलैंड तथा वियतनाम (जिन्हें एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित पोलिस्टर के सभी फुली ड्रॉन या फुली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (एफ डी आई) (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के कथित पाटन का आरोप लगाया गा है और संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है ।

2. और जबकि प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं इसलिए प्राधिकारी ऐसे किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने के लिए, जिसे यदि लगाया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, उक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच के लिए एतद्वारा इस जांच की शुरुआत करते हैं ।

घरेलू उद्योग

3. मै0 रिलायंस इंडस्ट्रीज लि0, मै0 गुप्ता सिंथेटिक्स लि0, मै0 नोवा पेट्रो केमिकल्स लि0 तथा मै0 चिरिपाल इंडस्ट्रीज लि0 की ओर से कृत्रिम फाइबर उद्योग एसोसिएशन द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है और घरेलू उद्योग की ओर से मै0 इंडो रामा सिंथेटिक्स लि0, मै0 गार्डन सिल्क, मै0 सेंचुरी एंका लि0, मै0 पेट्रोफिल लि0, मै0 जे बी एफ इंडस्ट्रीज लि0 और मै0 ए पी जे - एस एल जी ट्रेड लॉ, नई दिल्ली के जरिए मै0 वेलस्पन सिन्टेक्स लि0 द्वारा इस आवेदन का विधिवत समर्थन किया गया है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2 (ख) तथा नियम 5 (3) के अनुरूप घरेलू उद्योग की ओर से पाटनरोधी जाँच हेतु मामला प्रस्तुत करने की स्थिति में है।

विचाराधीन उत्पाद

4. विचाराधीन उत्पाद पॉलिस्टर के सभी फुली ड्रॉन या फुली ओरिएण्टेड यार्न/स्पिन ड्रॉन यार्न/फ्लैट यार्न (गैर टेक्सचर्ड एवं गैर पी ओ वाई) तथा सीमाशुल्क शीर्ष 5402.47 के टैरिफ विवरण के अनुरूप अन्य यार्न हैं (जिन्हें एतदपश्चात् "संबद्ध वस्तु" कहा गया है)। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। ऊपर उल्लिखित उत्पाद को वाणिज्यिक बाजार की भाषा शैली में "फुली ड्रॉन यार्न" के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तु का उपयोग वस्त्रों/घरेलू टेक्सटाइलों तथा अन्य औद्योगिक टेक्सटाइलों के विनिर्माण में होता है। संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों को उनके डेनियर्स, दृढ़ता, चमक, रंगों (जैसे थोड़ा मंद, चमकीला, अत्यधिक चमकीला, पूर्णतः मंद, रोगन संजित), अनुप्रस्थ काट तथा संकुचन के रूप में परिभाषित किया जाता है।

समान वस्तु

5. आवेदक ने दावा किया है कि भारत में पाटन की जा रही संबद्ध वस्तुएँ घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। पाटित वस्तुओं और घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तुओं के तकनीकी विनिर्देशनों, गुणवत्ता, कार्यों या अंतिम उपयोगों में कोई अंतर नहीं है। पाटित वस्तुओं और याचिकाकर्ताओं द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए उन्हें पाटनरोधी नियमों के तहत "समान वस्तु" माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तु की "घरेलू समान वस्तु" माना जा रहा है।

शामिल देश

6. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन गण, थाईलैंड तथा वियतनाम हैं।

सामान्य मूल्य

7. प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने प्रस्ताव किया है कि चीन जन गण और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ ताइवान को बाजार अर्थव्यवस्था वाला तीसरा देश माना जाए। इस प्रयोजनार्थ आवेदक ने ताइवान के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। थाईलैंड के लिए थाईलैंड के ही सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया है। प्राधिकारी ने आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए परिकलित मूल्यों के आधार पर संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है और प्राधिकारी द्वारा जाँच शुरुआत के प्रयोजनार्थ उस पर विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

8. इम्पोर्टल कम्प्यूटर लैब प्रा० लि०, मुम्बई से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत का दावा किया गया है। निवल निर्यात कीमत परिकलित करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पत्तन प्रहस्तन तथा प्रहस्तन प्रभार, बिक्री कमीशन आदि के लिए कीमत समायोजन का दावा किया है। निर्यात कीमतों तथा संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए आवेदकों द्वारा दावा किए गए समायोजनों के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।

पाटन मार्जिन

9. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमत से बहुत अधिक हैं जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

क्षति एवं कारणात्मक संबंध

10. आवेदकों ने कथित पाटन के परिणामस्वरूप पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास, कीमत अवमूल्यन तथा घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में अत्यधिक गिरावट के रूप में हुई क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण आवेदकों को हुई आर्थिक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य हैं।

जाँच अवधि

11. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि (पी ओ आई) 1 अक्टूबर, 2006 से 30 सितम्बर, 2007 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2004-मार्च, 05, अप्रैल 2005 - मार्च, 2006, अप्रैल 2006- मार्च 2007 तथा जाँच अवधि शामिल हैं।

शुल्क का भूतलक्षी अधिरोपण

12. आवेदक ने इस आधार पर शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने का अनुरोध किया है कि पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति पहले भी विद्यमान रहे हैं। यह भी कहा गया है कि कुछेक देशों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद आयातों में सापेक्ष तथा तुलनात्मक रूप से अत्यधिक वृद्धि हुई है जिससे स्पष्ट रूप से यह संकेत मिलता है कि बहुत ही छोटी अवधि में भारी मात्रा में पाटन से क्षति हुई है। हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपने निवेदन प्रस्तुत करें।

सूचना प्रस्तुत करना

13. ज्ञात संबंधित निर्यातकों एवं आयातकों और घरेलू उद्योग को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे निर्धारित प्रपत्र एवं रूप में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। वर्तमान जाँच में भाग लेने का इच्छुक कोई अन्य पक्षकार निम्नलिखित पते पर अपने निवेदन प्रस्तुत कर सकता है:-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

समय सीमा

14. इस समीक्षा से संबंधित सूचना लिखित में भेजी जानी चाहिए ताकि वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास पहुँच सके। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर की सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

16. सभी हितबद्ध पक्षकार उक्त नियमों के नियम 7(1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे।

17. ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से इंकार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जाँच में पर्याप्त रूप से बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को ऐसी सिफारिश कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझते हैं।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2008

Subject: Initiation of Anti-dumping investigations on imports of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (FDY) from China PR, Thailand and Vietnam.

No.14/3/2008-DGAD.— The Association of Synthetic Fibre Industries on behalf of M/s Reliance Industries Ltd., M/s Gupta Synthetics Ltd., M/s Nova Petrochemicals Ltd. and M/s Chiripal Industries Ltd. has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) for initiation of anti-dumping investigation concerning alleged dumping of All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (FDY) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Thailand and Vietnam (hereinafter referred to as subject countries).

2. AND, WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Domestic Industry

3. Application has been filed by The Association of Synthetic Fibre Industries on behalf of M/s Reliance Industries Ltd., M/s Gupta Synthetics Ltd., M/s Nova Petrochemicals Ltd. and M/s Chiripal Industries Ltd. duly supported by M/s Indo Rama Synthetics Ltd., M/s Garden Silk, M/s Century Enka Ltd., M/s Petrofil Ltd., M/s JBF Industries Ltd. and M/s Wellspun Syntex Ltd. through M/s APJ-SLG Trade Law, New Delhi on behalf of the domestic industry. As per the evidence available applicant has the standing to file the case for anti dumping investigation on behalf of domestic industry as per Rule 2(b) and Rule 5(3)(a) of Anti Dumping Rules.

Product under consideration

4. The product under consideration is All Fully Drawn or Fully Oriented Yarn/Spin Draw Yarn/Flat Yarn of Polyester (non-textured and non-POY) and other yarns conforming to the tariff description of Customs Heading 5402.47 (hereinafter also being referred to as "subject goods"). The Customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation. The above mentioned product in commercial market parlance is generally known as "Fully Drawn Yarn" (FDY). The subject goods are used for manufacture of apparel/household textiles, and other industrial textiles. Technical specifications of the subject goods are defined in terms of their deniers, tenacities, lustres, colours (like semi dull, bright, super bright, full dull, Dope dyed), cross section and shrinkage.

Like Articles

5. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. There is no difference in the dumped goods and the product under consideration manufactured by the petitioners. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like articles' under the Anti-dumping Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant in India are being treated as 'Domestic Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Countries involved

6. The countries involved in the present investigation are China PR, Thailand and Vietnam.

167745108-2

Normal Value

7. The Authority notes that the applicant has proposed that Taiwan be treated as market economy third country for determining normal value for China PR and Vietnam. For this purpose the applicant has constructed the normal value for Taiwan. For Thailand, the normal value has been constructed for Thailand. The Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries on the basis of constructed values as made available by the applicants and it has been considered by the Authority for the purpose of initiation.

Export Price

8. The export prices have been claimed on the basis of data obtained from Immortal Computer Lab Pvt. Ltd., Mumbai. Price adjustments have been claimed on account of Ocean freight, marine insurance, port handling and port charges, sales commissions etc. to arrive at the net export price. There is sufficient evidence of export prices and the adjustments claimed by the applicants for the subject goods from the subject countries.

Dumping Margin

9. There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries.

Injury and Causal Link

10. The applicants have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports, price undercutting, price underselling, price depression, price suppression and substantial decline in profitability for the domestic industries. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the applicants caused by dumped imports from subject countries.

Period of Investigation

11. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st October 2006 to 30th September 2007 (12 months). The injury investigation period will however cover the periods April, 2004–March, 05, April, 2005–March, 2006, April, 2006–March, 2007 and the POI.

Retrospective imposition of duties

12. The applicant has requested for retrospective imposition of duty on the ground that there is a history of dumping and injury to the domestic industry. It has also been stated that imports have gone up significantly in absolute as well as relative terms subsequent to the imposition of anti-dumping duties on certain countries clearly indicating that injury is caused by massive dumping in a relatively short time. The interested parties may make their submissions in this regard.

Submission of information

13. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form

and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

The Designated Authority
(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.

Time limit

14. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

INSPECTION OF PUBLIC FILE

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

16. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra.

17. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

R. GOPALAN, Designated Authority